



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

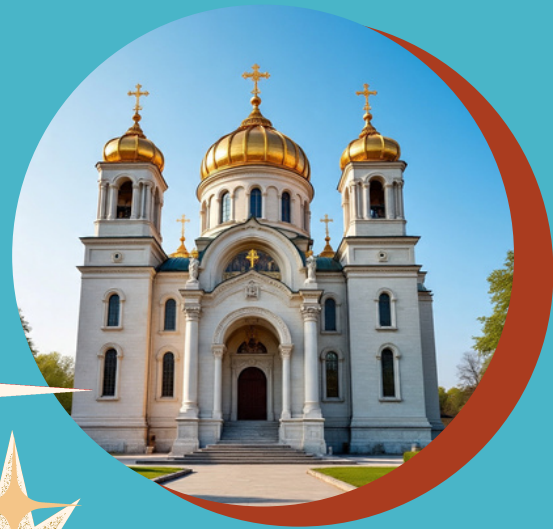


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

25 - 31 JAN 2026

4TH WEEK OF JANUARY

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques : What is the minimum initial and annual contribution required under the NPS Vatsalya Scheme as per PFRDA Guidelines 2025?

PFRDA द्वारा जारी NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 के अनुसार न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान कितना है?

- A) ₹100
- B) ₹250
- C) ₹500
- D) ₹1,000
- E) ₹2,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) issued the NPS Vatsalya Scheme Guidelines 2025 to strengthen long-term financial security for minors.
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नाबालिगों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 जारी किए।
- NPS Vatsalya is a contributory savings and long-term financial security scheme designed exclusively for minors.
- NPS वात्सल्य एक योगदान आधारित बचत एवं दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा योजना है, जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए तैयार किया गया है।
- The scheme was announced in the Union Budget 2024–25 and launched on 18 September 2024 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई थी और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया।
- The scheme is open to all Indian citizens, including NRI/OCI, below 18 years of age.
- यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिकों (NRI/OCI सहित खुली लिए के) है।
- The minor is the sole beneficiary; the account is opened in the minor's name and operated by the guardian.
- नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी होता है; खाता नाबालिग के नाम पर खुलता है और अभिभावक द्वारा संचालित होता है।
- The minimum initial and annual contribution under the scheme is ₹250, with no maximum limit.

- योजना के तहत न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान ₹250 है और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
- Contributions can also be gifted by relatives and friends.
- रिश्तेदार और मित्र भी उपहार के रूप में योगदान कर सकते हैं।
- Partial withdrawal is allowed after completion of three years from account opening.
- खाता खोलने के तीन वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।
- Up to 25% of own contributions (excluding returns) can be withdrawn.
- केवल स्वयं के योगदान का 25% तक (रिटर्न को छोड़कर) निकाला जा सकता है।
- Withdrawals are permitted for education, medical treatment, and specified disabilities.
- शिक्षा, चिकित्सा उपचार और निर्दिष्ट दिव्यांगता के लिए निकासी की अनुमति है।
- Partial withdrawal is allowed twice before 18 years and twice between 18–21 years, subject to conditions.
- 18 वर्ष से पहले दो बार और 18–21 वर्ष के बीच दो बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है।

Ques : Which institution has revamped its ATM infrastructure to make banking services more accessible and user-friendly across the country?
देशभर में बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए किस संस्था ने अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Department of Posts / डाक विभाग
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- In a major step towards enhancing financial inclusion, the Department of Posts has revamped its ATM infrastructure across India.
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाक विभाग

ने देशभर में अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है।

- A total of 887 ATMs have been installed at various post offices, enabling citizens to access essential banking services near their homes.
- विभिन्न डाकघरों में 887 ATM स्थापित किए गए हैं, जिससे नागरिकों को अपने घर के पास ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ मिल सकें।
- These ATMs allow customers to withdraw cash, check account balances, and perform other basic banking transactions conveniently.
- इन ATM के माध्यम से ग्राहक नकद निकासी, खाता शेष जांच और अन्य बुनियादी बैंकिंग लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।
- The initiative strengthens the role of post offices as important centers for last-mile banking services in rural and urban areas.
- यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लास्ट-माइल बैंकिंग सेवाओं के रूप में डाकघरों की भूमिका को मजबूत करती है।

Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed reopening the licensing window for new Urban Co-operative Banks (UCBs) after 22 years? 22 वर्षों बाद RBI ने नए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग विंडो फिर से खोलने का प्रस्ताव क्यों रखा है?

- A) To privatise Urban Co-operative Banks / शहरी सहकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए
- B) To increase foreign investment in UCBs / UCBs में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए
- C) After sector reforms, to allow eligible cooperative credit societies to become banks / क्षेत्रीय सुधारों के बाद योग्य सहकारी ऋण संस्थाओं को बैंक बनने की अनुमति देने के लिए
- D) Due to shortage of scheduled commercial banks / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कमी के कारण
- E) To merge all UCBs with public sector banks / सभी UCBs को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has proposed reopening the licensing window for new Urban Co-

operative Banks after 22 years.

- RBI ने 22 वर्षों बाद नए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।
- The previous licensing window was closed in 2004 due to widespread failures of newly licensed UCBs.
- वर्ष 2004 में नए लाइसेंस प्राप्त UCBs की व्यापक विफलताओं के कारण यह प्रक्रिया बंद कर दी गई थी।
- At that time, around 31% of newly licensed Urban Co-operative Banks had failed.
- उस समय लगभग 31% नए लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक असफल हो गए थे।
- Under the proposed norms, a cooperative credit society must have a minimum capital of ₹300 crore as on March 31 of the preceding financial year to apply for a banking licence.
- प्रस्तावित नियमों के अनुसार, किसी सहकारी ऋण संस्था के पास पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक न्यूनतम ₹300 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए।
- The assessed Capital Adequacy Ratio (CAR) should not be less than 12% at the time of grant of licence.
- लाइसेंस दिए जाने के समय आकलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 12% से कम नहीं होना चाहिए।
- The net Non-Performing Assets (NPA) ratio should not exceed 3%.
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का अनुपात 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- After multiple reforms in the cooperative banking sector, RBI is now reconsidering restarting the licensing process.
- सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधारों के बाद अब RBI लाइसेंसिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है।

Ques : By which platform will EPFO subscribers be able to withdraw EPF money directly into their bank accounts from April?

अप्रैल से EPFO सदस्य किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे?

- A) NEFT / एनईएफटी
- B) RTGS / आरटीजीएस
- C) IMPS / आईएमपीएस
- D) UPI / यूपीआई
- E) AEPS / आईपीएस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- EPFO subscribers will be able to withdraw their Employees' Provident Fund (EPF) directly into bank accounts through the UPI payment gateway by April.
 - EPFO सदस्य अप्रैल तक UPI पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे।
 - The auto-settlement withdrawal limit has been increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh, enabling higher instant withdrawals.
 - ऑटो को सीमा निकासी सेटलमेंट-₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
 - This move will allow EPFO members to access funds within three days for purposes such as illness, education, marriage, and housing.
 - इस कदम से EPFO सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए 3 दिनों के भीतर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
 - The Labour Ministry is working on a system where a part of EPF savings will be frozen, while a major portion will be available for quick withdrawal via UPI.
 - श्रम मंत्रालय ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें EPF का एक हिस्सा फ्रीज रहेगा, जबकि बड़ा हिस्सा UPI के जरिए त्वरित निकासी के लिए उपलब्ध होगा।
 - The current interest rate on EPF deposits is 8.25% per annum.
 - वर्तमान में EPF पर ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।
-

Ques : When will the Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026 come into effect?

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 कब से प्रभावी होगी?

- A) January 1, 2026
- B) April 1, 2026
- C) July 1, 2025
- D) October 1, 2026
- E) July 1, 2026

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026, a revised grievance redressal framework aimed at simplifying complaint resolution for customers of banks and other financial institutions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- The RB-IOS 2026 supersedes the earlier RB-IOS 2021 and will be effective from July 1, 2026.
- RB-IOS 2026, RB-IOS 2021 का स्थान लेगी और 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
- The Scheme applies to various Regulated Entities, including commercial banks, co-operative banks, eligible NBFCs, non-bank PPI issuers, and credit information companies.
- यह योजना विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, पात्र NBFC, नॉन-बैंक PPI जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ शामिल हैं।
- There is no monetary limit on disputes that can be taken to the RBI Ombudsman.
- RBI लोकपाल के समक्ष लाए जाने वाले विवादों की कोई राशि सीमा नहीं है।
- The compensation limit for consequential loss has been increased to ₹30 lakh (previously Rs 20 lakh), and up to ₹3 lakh (previously Rs 1 lakh), can be awarded for mental agony, harassment, and expenses.
- परिणामी नुकसान के लिए मुआवज़ा सीमा ₹30 लाख कर दी गई है, जबकि मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न आदि के लिए ₹3 लाख तक का मुआवज़ा दिया जा सकता है।
- RBI will set up a Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) for handling complaints under the scheme.
- RBI शिकायतों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित करेगा।
- RBI Ombudsman and Deputy Ombudsman will be appointed for a three-year term.
- RBI लोकपाल और उप-लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

Ques: Public Sector Banks (PSBs) sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications worth more than ₹52,300 crore under which digital initiative during April–December 2025?

अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किस डिजिटल पहल के तहत 3.96

लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन स्वीकृत किए?

- A) Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) / आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
- B) Jan Samarth Portal / जन समर्थ पोर्टल
- C) Credit Assessment Model (CAM) based digital underwriting / क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) आधारित डिजिटल अंडरराइटिंग
- D) MSME Credit Guarantee Scheme / MSME क्रेडिट गारंटी योजना
- E) Account Aggregator Framework / अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Public Sector Banks sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications amounting to more than ₹52,300 crore between April 1 and December 31, 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच 3.96 लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन, ₹52,300 करोड़ से अधिक राशि के, स्वीकृत किए।
- These loans were sanctioned under digital credit underwriting programmes.
- ये ऋण डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए।
- In 2025, PSBs launched the Credit Assessment Model (CAM) for MSMEs.
- वर्ष 2025 में PSBs ने MSMEs के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) शुरू किया।
- CAM is based on digital footprints of Micro, Small and Medium Enterprises.
- CAM सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित है।
- The initiative aims to enable faster, data-driven and transparent credit flow to MSMEs.
- इस पहल का उद्देश्य MSMEs को तेज़, डेटा-आधारित और पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है।

Ques : Which foreign bank has received approval to acquire a majority stake in RBL Bank Limited?

किस विदेशी बैंक को RBL बैंक लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है?

- A) Emirates NBD Bank / एमिरेट्स NBD बैंक
- B) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- C) HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
- D) DBS Bank / डीबीएस बैंक
- E) Barclays Bank / बार्कलेज बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Commission has approved the proposed acquisition of shareholding in RBL Bank Limited by Emirates NBD Bank (P.J.S.C.).
- आयोग ने एमिरेट्स NBD बैंक (P.J.S.C.) द्वारा RBL बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
- The proposed combination involves acquisition of up to 74% (minimum 51%) shareholding in RBL Bank.
- प्रस्तावित सौदे के तहत RBL बैंक में न्यूनतम 51% और अधिकतम 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।
- This acquisition will be carried out through a mandatory open offer (up to 26%) under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, along with a preferential allotment of up to 60% equity shares.
- यह अधिग्रहण SEBI (SAST) विनियम, 2011 के तहत अनिवार्य ओपन ऑफर (26% तक) और प्राथमिक आवंटन (60% तक इक्विटी शेयर) के माध्यम से किया जाएगा।
- Additionally, Emirates NBD's banking operations in India, currently operating through three branches, will be amalgamated with RBL Bank on a going concern basis.
- इसके अतिरिक्त, भारत में एमिरेट्स NBD की तीन शाखाओं के माध्यम से संचालित बैंकिंग परिचालन को RBL बैंक में विलय किया जाएगा।
- Emirates NBD Bank is a public joint stock company, listed on the Dubai Financial Market, and is headquartered in Dubai, UAE.
- एमिरेट्स NBD बैंक एक पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट में सूचीबद्ध है और इसका मुख्यालय दुबई, UAE में स्थित है।

About RBL Bank Limited:

- Established : 1943
- HQ : Mumbai, Maharashtra

- MD & CEO : R Subramaniakumar
- Tagline : Apno ka bank

Ques : From which date will the new FEMA Export-Import Regulations, 2026 come into effect?

नई FEMA निर्यात-आयात विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?

- A) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
- B) 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026
- C) 1 October 2026 / 1 अक्टूबर 2026
- D) 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027
- E) 15 August 2026 / 15 अगस्त 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has notified the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात-आयात) विनियम, 2026 को अधिसूचित किया है।
- The new FEMA trade regulations will come into effect from 1 October 2026.
- नई FEMA व्यापार नियमावली 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
- Authorised Dealer (AD) banks must enter Export Declaration Form (EDF) details for goods exported through non-EDI ports into the Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) within five working days.
- अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को नॉन-EDI पोर्ट्स से निर्यात किए गए माल का EDF विवरण 5 कार्यदिवस के भीतर EDPMS प्रणाली में दर्ज करना होगा।
- AD banks are also required to upload EDF details of services exports into EDPMS within five working days of receipt from exporters.
- AD बैंकों को निर्यातकों से प्राप्त सेवा निर्यात के EDF विवरण भी 5 कार्यदिवस के भीतर EDPMS में अपलोड करने होंगे।
- The move aims to strengthen export-import data monitoring, improve compliance, and enhance transparency under FEMA.
- इस कदम का उद्देश्य FEMA के तहत निर्यात-आयात डेटा निगरानी को मजबूत करना,

अनुपालन बढ़ाना और पारदर्शिता में सुधार करना है।

Ques : According to the International Monetary Fund (IMF)'s World Economic Outlook (WEO) titled "Global Economy: Steady amid Divergent Forces", what is the revised GDP growth projection for India for FY 2025–26?

“ग्लोबल इकोनॉमी :स्टेडी अमिड डाइवर्जेंट फोर्सस” शीर्षक वाली IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 6.4%
- B) 6.6%
- C) 7.0%
- D) 7.3%
- E) 7.4%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The International Monetary Fund (IMF) released its World Economic Outlook (WEO) titled “Global Economy: Steady amid Divergent Forces”.
 - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने “ग्लोबल इकोनॉमी: स्टेडी अमिड डाइवर्जेंट फोर्सस” शीर्षक से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) जारी की।
 - The IMF upwardly revised India’s GDP growth forecast for FY 2025–26 to 7.3%, from 6.6% projected in October 2025.
 - IMF ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अक्टूबर 2025 के 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया।
 - This projection is slightly lower than the Government of India’s estimate of 7.4% for the same period.
 - यह अनुमान भारत सरकार के 7.4% के आकलन से थोड़ा कम है।
 - The IMF further projected that India’s growth would moderate to 6.4% in both FY 2026–27 and FY 2027–28.
 - IMF के अनुसार FY27 और FY28 में भारत की वृद्धि दर 6.4% पर आ सकती है।
-

Ques: What is the key proposal in the RBI's draft amendment directions regarding the calculation of Owned Fund / Tier-1 Capital for NBFCs and ARCs? NBFCs और ARCs के लिए ओन्ड फंड / टियर-1 कैपिटल की गणना से संबंधित RBI के मसौदा संशोधन निर्देशों का प्रमुख प्रस्ताव क्या है?

- A) Excluding free reserves completely from Owned Fund / ओन्ड फंड से फ्री रिज़र्व को पूरी तरह हटाना
- B) Allowing Tier-1 Capital calculation only once every three years / टियर-1 कैपिटल की गणना केवल तीन वर्षों में एक बार करना
- C) Including free reserves and quarterly profits in Owned Fund with conditions / शर्तों के साथ फ्री रिज़र्व और त्रैमासिक लाभ को ओन्ड फंड में शामिल करना
- D) Increasing credit concentration limits for NBFCs / NBFCs के लिए क्रेडिट एकाग्रता सीमा बढ़ाना
- E) Removing concentration norms for ARCs / ARCs के लिए एकाग्रता मानदंड समाप्त करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India issued draft amendment directions to clarify the calculation of Owned Fund / Tier-1 Capital for NBFCs and Asset Reconstruction Companies (ARCs).
- RBI ने NBFCs और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के लिए ओन्ड फंड / टियर-1 कैपिटल की गणना स्पष्ट करने हेतु मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए।
- The draft aims to ensure proper compliance with credit and investment concentration limits.
- इसका उद्देश्य क्रेडिट और निवेश एकाग्रता सीमाओं के पालन को सुनिश्चित करना है।
- RBI has invited public comments on the draft till 28 January 2026.
- RBI ने इस मसौदे पर 28 जनवरी 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।
- Currently, NBFCs (other than NBFC-UL) and ARCs calculate Tier-1 Capital based on figures as of 31 March of the previous year.
- वर्तमान में NBFCs (NBFC-UL को छोड़कर) और ARCs पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टियर-1 कैपिटल की गणना करते हैं।
- Under the new draft, free reserves, including quarterly profits, may be included in Owned Fund, subject to specified conditions.
- नए मसौदे के तहत, निर्धारित शर्तों के अधीन फ्री रिज़र्व, जिसमें त्रैमासिक लाभ भी शामिल

हैं, को ओन्ड फंड में जोड़ा जा सकता है।

- Eligible profits will be reduced by 25% of the average dividend paid over the last three years, multiplied by the number of completed quarters in the year.
- पात्र लाभ से पिछले तीन वर्षों में दिए गए औसत लाभांश का 25%, वर्ष में पूर्ण हुए तिमाहियों की संख्या से गुणा कर, घटाया जाएगा।

Ques : What was the unemployment rate (UR) among persons aged 15 years and above in India as per the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletin – December 2025?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मासिक बुलेटिन – दिसंबर 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोज़गारी दर कितनी रही?

- A) 4.5%
- B) 4.7%
- C) 4.8%
- D) 5.1%
- E) 6.7%

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या

- The National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the 9th edition of the PLFS Monthly Bulletin – December 2025.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने PLFS मासिक बुलेटिन – दिसंबर 2025 का 9वाँ संस्करण जारी किया।
- The overall unemployment rate (UR) for persons aged 15 years and above remained stable at 4.8% in December 2025, compared to 4.7% in November 2025.
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल बेरोज़गारी दर 4.8% रही, जो नवंबर 2025 के 4.7% के लगभग समान है।
- The rural unemployment rate remained unchanged at 3.9%.
- ग्रामीण बेरोज़गारी दर 3.9% पर स्थिर रही।
- The urban unemployment rate increased to 6.7%, up from 6.5% in the previous month.

- शहरी बेरोज़गारी दर 6.5% से बढ़कर 6.7% हो गई।
- Unemployment Rate (UR) is defined as the percentage of people in the labour force who are without work but are available for and actively seeking employment.
- बेरोज़गारी दर (UR) का अर्थ है—श्रम बल में शामिल वे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम के लिए उपलब्ध हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

Ques : Who has been appointed as the part-time Chairman of IndusInd Bank effective January 31?

31 जनवरी से इंडसइंड बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन टाइटम-?

- A) Rajiv Anand / राजीव आनंद
- B) Sunil Mehta / सुनील मेहता
- C) Arijit Basu / अरिजीत बसु
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Dinesh Kumar Khara / दिनेश कुमार खारा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- IndusInd Bank has appointed veteran banker Arijit Basu as its part-time Chairman with effect from January 31.
- इंडसइंड बैंक ने वरिष्ठ बैंकर अरिजीत बसु को 31 जनवरी से अपना पार्ट टाइम चेयरमैन टाइटम- है। किया नियुक्त
- He will succeed Sunil Mehta after the completion of his tenure.
- वह सुनील मेहता के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनका स्थान लेंगे।
- Arijit Basu has over 42 years of banking experience, including 37 years with the State Bank of India (SBI).
- अरिजीत बसु के पास 42 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव है, जिसमें 37 वर्ष SBI में शामिल हैं।
- He joined SBI in 1983 and retired in 2020 as Managing Director.
- उन्होंने 1983 में SBI जॉइन किया और 2020 में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- He earlier served as Managing Director & CEO of SBI Life Insurance from 2014 to 2018.

- वह 2014 से 2018 तक SBI लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO भी रह चुके हैं।
- He also served as Chairman of HDB Financial Services, the NBFC arm of HDFC Bank.
- वह HDFC बैंक की NBFC शाखा, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
- The appointment comes at a time when IndusInd Bank has witnessed leadership changes following governance-related issues.
- यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों के बाद इंडसइंड बैंक में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिले हैं।

Ques: Suryoday Small Finance Bank has partnered with which company to deploy an AI-powered Video KYC (VKYC) solution?

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-आधारित वीडियो KYC (VKYC) समाधान लागू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) HyperVerge / हाइपरवर्ज
- B) TCS / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
- C) Infosys / इंफोसिस
- D) Paytm / पेटीएम
- E) Razorpay / रेज़रपे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Suryoday Small Finance Bank has partnered with HyperVerge to implement an AI-powered Video KYC (VKYC) solution.
- सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-आधारित वीडियो KYC समाधान लागू करने के लिए HyperVerge के साथ साझेदारी की है।
- The collaboration aims to modernize the customer onboarding process while maintaining strong regulatory compliance.
- इस सहयोग का उद्देश्य ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- The AI-driven VKYC solution also enhances data security and operational efficiency.
- AI-आधारित VKYC समाधान डेटा सुरक्षा और परिचालन दक्षता को भी मजबूत करता है।

About Suryoday Small Finance Bank :

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- MD & CEO : Baskar Babu Ramachandran
- Tagline : A Bank of Smiles

Ques: Which TReDS platform became the first in India to declare and pay an interim dividend, marking a historic milestone in the TReDS ecosystem?

भारत का कौन सा TReDS प्लेटफॉर्म अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान करने वाला पहला बना, जिससे TReDS पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई?

- A) M1xchange / एम1एक्सचेंज
- B) A.TReDS / ए.टी.आर.डी.एस.
- C) Receivables Exchange of India Limited (RXIL) / रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
- D) Invoicemart / इनवॉइसमार्ट
- E) SIDBI TReDS / एसआईडीबीआई टी.आर.डी.एस.

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Receivables Exchange of India Limited (RXIL), a Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform, declared and paid an interim dividend of 21.6% on the face value of its shares.
- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म RXIL ने अपने शेयरों के अंकित मूल्य पर 21.6% का अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया।
- RXIL is the first TReDS platform in India to return capital to its stakeholders, marking a historic milestone in India's TReDS ecosystem.
- RXIL भारत का पहला TReDS प्लेटफॉर्म है जिसने हितधारकों को पूंजी लौटाई, जो TReDS पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक कदम है।
- RXIL received RBI approval in December 2016 and executed its first TReDS transaction on 9 January 2017.

- RXIL को दिसंबर 2016 में RBI की मंजूरी मिली थी और उसने 9 जनवरी 2017 को पहला TReDS लेनदेन किया।
- RXIL is a joint venture of SIDBI and NSE, along with SBI, ICICI Bank, and Yes Bank as partners.
- RXIL, SIDBI और NSE का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें SBI, ICICI बैंक और Yes बैंक भागीदार हैं।

Ques : Which Indian fintech firm received NPCI approval to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP)?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन की मंजूरी किस भारतीय फिनटेक कंपनी को मिली?

- A) PhonePe / फोनपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) ZET / ज़ेट
- D) BharatPe / भारतपे
- E) Cred / क्रेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Credit-focused Indian fintech firm ZET secured approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
- क्रेडिट-केंद्रित भारतीय फिनटेक कंपनी ZET को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन हेतु NPCI से मंजूरी मिली।
- The service is enabled through a banking partnership with RBL Bank, earlier known as Ratnakar Bank Limited.
- यह सेवा आरबीएल बैंक (पूर्व में रत्नाकर बैंक लिमिटेड) के साथ बैंकिंग साझेदारी के माध्यम से सक्षम की गई है।
- The platform is powered by Juspay's technology infrastructure for transaction processing.
- यह प्लेटफॉर्म लेन-देन प्रसंस्करण के लिए Juspay की तकनीकी अवसंरचना पर

आधारित है।

Ques : Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of Karnataka Bank Limited?

कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Srikrishnan Hari Hara Sarma / श्रीकृष्णन हरि हर सरमा
- B) Raghavendra Srinivas Bhat / राघवेंद्र श्रीनिवास भट
- C) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन
- D) Ashok Chandra / अशोक चंद्र
- E) Murali Natrajan / मुरली नटराजन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Mr. Raghavendra Srinivas Bhat has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of Karnataka Bank Limited.
 - श्री राघवेंद्र श्रीनिवास भट को कर्नाटक बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
 - He replaced Srikrishnan Hari Hara Sarma.
 - उन्होंने श्रीकृष्णन हरि हर सरमा का स्थान लिया है।
 - Karnataka Bank was established in 1924.
 - कर्नाटक बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी।
 - The headquarters of Karnataka Bank is located in Mangaluru, Karnataka.
 - कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
 - The tagline of Karnataka Bank is “Your Family Bank Across India”.
 - कर्नाटक बैंक का टैगलाइन “Your Family Bank Across India” है।
-

Ques : After the 4th phase of consolidation, how many Regional Rural Banks (RRBs) are operational in India?

चौथे चरण के विलय के बाद भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) कार्यरत हैं?

- A) 43
- B) 35
- C) 28
- D) 30
- E) 25

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Finance Ministry held its first high-level meeting with heads of Public Sector Banks (PSBs) and Regional Rural Banks (RRBs) after the 4th phase of RRB consolidation, effective from May 1.
- वित्त मंत्रालय ने 1 मई से लागू RRB विलय के चौथे चरण के बाद PSB और RRB प्रमुखों के साथ पहली उच्चकी। बैठक स्तरीय-
- After the latest consolidation, the number of RRBs reduced from 43 to 28.
- नवीनतम विलय के बाद RRB की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई।
- On May 1, 15 RRBs across 11 states were merged to form state-owned RRBs to improve efficiency and reduce operational costs.
- 1 मई को 11 राज्यों के 15 RRB का विलय कर दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से राज्य वाले स्वामित्व-RRB बनाए गए।

- Phase-wise RRB consolidation:
 - Phase 1 (FY 2006–10): 196 → 82
 - Phase 2 (FY 2013–15): 82 → 56
 - Phase 3: 56 → 43

- चरणबद्ध RRB विलय:
 - चरण 1 (FY 2006–10): 196 → 82
 - चरण 2 (FY 2013–15): 82 → 56
 - चरण 3: 56 → 43

- RRBs were established under the RRB Act, 1976 to provide credit to small farmers, agricultural labourers, and artisans.
- RRB की स्थापना RRB अधिनियम, 1976 के तहत छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई।
- The Act was amended in 2015, allowing RRBs to raise capital from sources other than the Centre, States, and sponsor banks.

- 2015 के संशोधन से RRB को केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति मिली।
- Authorised capital was increased from ₹5 crore to ₹2,000 crore, with minimum authorised capital raised to ₹1 crore.
- अधिकृत पूंजी ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ की गई और न्यूनतम अधिकृत पूंजी ₹1 करोड़ तय की गई।
- Even after dilution, the combined stake of the Centre and sponsor banks cannot fall below 51%.
- हिस्सेदारी घटने के बाद भी केंद्र और प्रायोजक बैंकों की संयुक्त हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती।
- Current shareholding pattern: Centre (50%), Sponsor Banks (35%), State Governments (15%).
- वर्तमान हिस्सेदारी संरचना) केंद्र :50%), प्रायोजक बैंक)35%), राज्य सरकार)15%)।
- The Finance Ministry also unveiled a new unified logo for RRBs symbolising trust, growth, progress, support, and empowerment.
- वित्त मंत्रालय ने RRB के लिए नया एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया, जो विश्वास, विकास, प्रगति, सहयोग और सशक्तिकरण को दर्शाता है।

Ques : What was the growth rate of Foreign Direct Investment (FDI) inflows into India in 2025?

2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह की वृद्धि दर क्या रही?

- A) 25%
- B) 40%
- C) 55%
- D) 73%
- E) 90%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- FDI inflows into India rose by 73% to USD 47 billion in 2025.
- 2025 में भारत में FDI प्रवाह 73% बढ़कर 47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- The growth was driven mainly by investments in manufacturing, services, digital infrastructure, IT and R&D.

- यह वृद्धि विनिर्माण, सेवाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और R&D में निवेश के कारण हुई।
- In contrast, FDI inflows into China declined for the third consecutive year, falling 8% to USD 107.5 billion.
- इसके विपरीत, चीन में FDI प्रवाह लगातार तीसरे वर्ष 8% घटकर 107.5 अरब डॉलर रहा।
- Globally, FDI flows increased by 14% to about USD 1.6 trillion in 2025, with uneven regional growth.
- वैश्विक स्तर पर FDI प्रवाह 14% बढ़कर लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर रहा, हालांकि क्षेत्रीय असमानता बनी रही।
- The United States remained the largest FDI recipient, led by cross-border M&A in technology and semiconductors.
- प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सीमा अमेरिका कारण के अधिग्रहण एवं विलय पार-बड़ा सबसे FDI प्राप्तकर्ता बना रहा।

Ques : Which company has received in-principle approval from the Reserve Bank of India to operate as a Payment Aggregator – Cross Border (PA-CB)? भारतीय रिज़र्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किस कंपनी को मिली है?

- A) Payoneer India Private Limited / पेयोनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) Paytm Payments Services / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज
- D) Stripe India / स्ट्राइप इंडिया
- E) Worldline India / वर्ल्डलाइन इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- RBI granted in-principle approval to Payoneer India Private Limited, a subsidiary of US-based Payoneer Global, to operate as a PA–Cross Border.
- RBI के अनुसार, पेयोनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Payoneer Global की सहायक कंपनी को (PA–क्रॉस बॉर्डर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
- Non-bank PAs must maintain minimum net worth norms, follow ₹25 lakh per-transaction limit, and keep separate import–export accounts without netting.

- गैर बैंक-PA को न्यूनतम नेट वर्थ मानदंड, ₹25 लाख प्रति लेनआयात और सीमा देन-- निर्यात के लिए अलग खाते बनाए रखने होंगे।

Ques : What is the percentage hike approved in the wage bill for employees of Public Sector General Insurance Companies (PSGICs)?

पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs) के कर्मचारियों के वेतन बिल में कितनी प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है?

- A) 8% / 8%
- B) 10% / 10%
- C) 12.41% / 12.41%
- D) 14% / 14%
- E) 18% / 18%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Central Government has approved the wage revision for Public Sector General Insurance companies (PSGICs) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Additionally, it has approved pension revision for retirees of Reserve Bank of India (RBI) and NABARD.
- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
- The Central Government approved wage revision for PSGIC employees effective from 01.08.2022.
- केंद्र सरकार ने PSGIC कर्मचारियों के लिए 01.08.2022 से वेतन संशोधन को मंजूरी दी है।
- The overall increase in the wage bill is 12.41%, including a 14% hike in Basic Pay and Dearness Allowance.
- कुल वेतन बिल में 12.41% की वृद्धि की गई है, जिसमें बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की बढ़ोतरी शामिल है।
- NPS contribution for employees who joined after 01.04.2010 has been enhanced from 10% to 14%.
- 01.04.2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया

गया है।

- Family pension has been revised to a uniform rate of 30% from the date of official gazette notification.
- फैमिली पेंशन को राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से समान रूप से 30% कर दिया गया है।
- The total financial outgo for PSGIC-related revisions is estimated at Rs 8,170.30 crore.
- PSGIC से जुड़े संशोधनों पर कुल वित्तीय भार लगभग 8,170.30 करोड़ रुपये आंका गया है।

NABARD

- All Group "A," "B," and "C" employees at NABARD will have a wage and benefit increase of roughly 20% starting on November 1, 2022.
- NABARD के सभी ग्रुप "A," "B," और "C" कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 1 नवंबर, 2022 से लगभग 20% की वृद्धि होगी।
- NABARD retirees who were initially hired by the organization and retired prior to November 1st, 2017, now get a basic pension or family pension that is comparable to that of former RBI NABARD retirees.
- NABARD के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें संगठन द्वारा शुरू में नियुक्त किया गया था और जो 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें अब पूर्व RBI NABARD के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

RBI

- With effect from November 1st, 2022, the authorized revision will increase pensions and family pensions by 10% on base pension plus dearness relief.
- 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी, स्वीकृत संशोधन के अनुसार मूल पेंशन और महंगाई राहत में 10% की वृद्धि के साथ पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि होगी।
- The anticipated overall financial impact is ₹2,696.82 crore, comprising a recurrent annual cost of ₹211.80 crore and a one-time expenditure of ₹2,485.02 crore towards arrears.
- अनुमानित कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,696.82 करोड़ है, जिसमें ₹211.80 करोड़ की आवर्ती वार्षिक लागत और बकाया राशि के लिए ₹2,485.02 करोड़ का एकमुश्त व्यय शामिल है।

Ques : Pine Labs has partnered with which bank to build a payment acquiring system in the UAE?

UAE में पेमेंट अक्रायरिंग सिस्टम बनाने के लिए Pine Labs ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

- A) Emirates NBD / एमिरेट्स एनबीडी
- B) First Abu Dhabi Bank / फर्स्ट अबू धाबी बैंक
- C) Mashreq Bank / माशरेक बैंक
- D) Wio Bank / Wio बैंक
- E) Abu Dhabi Commercial Bank / अबू धाबी कमर्शियल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Indian payments technology company Pine Labs has partnered with UAE-based Wio Bank to build a payment acquiring system.
 - भारतीय भुगतान तकनीक कंपनी पाइन लैब्स ने UAE स्थित Wio बैंक के साथ पेमेंट अक्रायरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए साझेदारी की है।
 - As part of the partnership, Wio Bank will deploy Credit+, Pine Labs' API-based acquiring platform.
 - इस साझेदारी के तहत Wio बैंक Pine Labs का API आधारित प्लेटफॉर्म Credit+ तैनात करेगा।
 - Acquiring platforms help merchants process digital payments efficiently.
 - अक्रायरिंग प्लेटफॉर्म व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रोसेस करने में सहायता करते हैं।
 - Pine Labs currently offers Credit+ services in India, Sri Lanka, Middle East, Africa, and Southeast Asia.
 - Pine Labs वर्तमान में भारत, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिणमे एशिया पूर्व-ं Credit+ सेवाएं प्रदान करता है।
 - The partnership strengthens digital payment infrastructure in the UAE.
 - यह साझेदारी UAE के डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करेगी।
-

Ques: PhonePe recently received SEBI approval to launch its IPO. Which of the following statements about the IPO is/are correct?

हाल ही में PhonePe को अपना IPO लॉन्च करने के लिए SEBI की मंजूरी मिली। IPO से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. The IPO aims to raise about ₹12,000 crore, mainly through a pure Offer for Sale (OFS).

1. आईपीओ का उद्देश्य मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से लगभग ₹12,000 करोड़ जुटाना है।
 2. The IPO will include fresh capital infusion into the company.
2. आईपीओ के माध्यम से कंपनी में नई पूंजी का निवेश होगा।
 3. Walmart will sell around 9.06% stake (about 4.59 crore shares) through the IPO.
3. वॉलमार्ट आईपीओ के जरिए लगभग 9.06% हिस्सेदारी (लगभग 4.59 करोड़ शेयर) बेचेगी।
 4. Microsoft and Tiger Global will completely exit PhonePe by selling their shares.
4. माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल अपने शेयर बेचकर PhonePe से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे।
- A) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
B) 1, 3 and 4 only / केवल 1, 3 और 4
C) 2 and 4 only / केवल 2 और 4
D) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
E) 1, 2, 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- PhonePe has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch its IPO.
- PhonePe को अपना IPO लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी मिली है।
- The company is targeting a fund-raise of ₹12,000 crore, revised upward from ₹10,000 crore.
- कंपनी ₹12,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जो पहले ₹10,000 करोड़ था।
- The IPO will be primarily a pure Offer for Sale (OFS) with no fresh capital infusion.
- यह IPO मुख्य रूप से शुद्ध ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें कोई नया पूंजी निवेश नहीं होगा।

- Walmart, PhonePe's largest shareholder, will sell about 9.06% stake (around 4.59 crore shares).
- PhonePe की सबसे बड़ी शेयरधारक Walmart लगभग 9.06% हिस्सेदारी (लगभग 4.59 करोड़ शेयर) बेचेगी।
- Microsoft and Tiger Global will fully exit PhonePe by selling a combined 47 lakh shares in the IPO.
- Microsoft और Tiger Global IPO के जरिए कुल 47 लाख शेयर बेचकर PhonePe से पूरी तरह बाहर निकलेंगे।
- The IPO is being managed by banks such as Kotak Mahindra Capital, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital, and Goldman Sachs.
- इस IPO का प्रबंधन Kotak Mahindra Capital, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital और Goldman Sachs जैसे बैंक कर रहे हैं।

Ques : SAARG (Strategic Asset Allocation and Risk Governance) has been formed by which regulatory body?

SAARG (स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस द्वारा संस्था नियामक किस गठन का (है गया किया?)

- A) SEBI / सेबी
- B) RBI / आरबीआई
- C) IRDAI / आईआरडीएआई
- D) PFRDA / पीएफआरडीए
- E) IFSCA / आईएफएससीए

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- SAARG has been constituted by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- SAARG का गठन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया गया है।
- It is a 10-member committee chaired by Shri Narayan Ramachandran, former Country Head and CEO of Morgan Stanley India.
- यह 10 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता मॉर्गन स्टेनली इंडिया के पूर्व कंट्री हेड एवं CEO श्री नारायण रामचंद्रन कर रहे हैं।

- The committee has a deadline of 9 months to submit its recommendations.
- समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए 9 महीने की समय है। गई दी सीमा-
- Its objective is to strengthen investment architecture, promote long-term retirement wealth creation, enhance diversification, improve risk management practices, and expand subscriber choice.
- इसका उद्देश्य निवेश ढांचे को मजबूत करना, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति संपत्ति सृजन को बढ़ावा देना, विविधीकरण सुधारना, जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना और ग्राहकों के विकल्पों का विस्तार करना है।

About PFRDA :

- Established : 2003
- HQ : New Delhi
- Chairman : Sivasubramanian Ramann

Ques: According to the RBI report “State Finances: A Study of Budgets of 2025–26”, what is the gross fiscal deficit of States budgeted for 2025–26 as a percentage of GDP?

RBI की रिपोर्ट “स्टेट फाइनेंस: बजट्स का अध्ययन 2025–26” के अनुसार 2025–26 के लिए राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है?

- A) 2.5%
- B) 2.8%
- C) 3.0%
- D) 3.3%
- E) 3.8%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India released the report titled “State Finances: A Study of Budgets of 2025–26”.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने “स्टेट फाइनेंस: बजट्स का अध्ययन 2025–26” नामक रिपोर्ट जारी की।
- The theme of the report is “Demographic Transition in India – Implications

for State Finances.”

- रिपोर्ट की थीम “भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन – राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव” है।
- States’ consolidated gross fiscal deficit rose to 3.3% of GDP in 2024–25 after staying below 3.0% during the previous three years.
- पिछले तीन वर्षों तक 3.0% से नीचे रहने के बाद 2024–25 में राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% हो गया।
- For 2025–26, States have budgeted a gross fiscal deficit of 3.3% of GDP.
- 2025–26 के लिए राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% निर्धारित किया है।
- The thrust on capital expenditure has been sustained, with capex steady at 2.7% of GDP in 2023–24 and 2024–25.
- पूंजीगत व्यय पर ज़ोर बना रहा, जो 2023–24 और 2024–25 में GDP का 2.7% रहा।
- Capital expenditure is budgeted to increase to 3.2% of GDP in 2025–26.
- 2025–26 में पूंजीगत व्यय को GDP के 3.2% तक बढ़ाने का बजट रखा गया है।
- The consolidated outstanding liabilities of States are estimated at 29.2% of GDP by end-March 2026.
- मार्च 2026 के अंत तक राज्यों की संयुक्त बकाया देनदारियाँ GDP के 29.2% रहने का अनुमान है।

Ques : What is the main purpose of introducing hybrid ATMs by the government?

सरकार द्वारा हाइब्रिड ATM शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Promote credit card usage / क्रेडिट कार्ड उपयोग को बढ़ावा देना
- B) Increase digital wallet adoption / डिजिटल वॉलेट अपनाने को बढ़ाना
- C) Improve availability of small-denomination currency notes / छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाना
- D) Reduce ATM maintenance costs / ATM रखरखाव लागत कम करना
- E) Replace traditional ATMs / पारंपरिक ATM को बदलना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The central government is planning to introduce hybrid ATMs to improve the

availability of small-denomination currency notes.

- केंद्र सरकार छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ATM शुरू करने की योजना बना रही है।
- These hybrid ATMs will be able to dispense ₹10, ₹20 and ₹50 notes on demand.
- ये हाइब्रिड ATM मांग पर ₹10, ₹20 और ₹50 के नोट उपलब्ध कराएंगे।
- They will also facilitate the exchange of large denomination notes into smaller notes and coins.
- ये बड़े मूल्य के नोटों को छोटे नोटों और सिक्कों में बदलने की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- The move aims to address the persistent shortage of small notes faced during daily cash transactions.
- इस पहल का उद्देश्य रोजमर्रा के नकद लेन वाली रहने बनी लगातार की नोटों छोटे में देन-है। करना दूर को कमी
- The initiative comes nearly a decade after demonetisation, which significantly altered cash circulation patterns.
- यह पहल नोटबंदी के लगभग एक दशक बाद लाई जा रही है, जिसने नकदी के प्रचलन के स्वरूप को काफी प्रभावित किया था।
- Despite the rapid growth of UPI and digital payments, the demand for small-denomination cash remains high.
- UPI और डिजिटल भुगतान के तेज़ विस्तार के बावजूद छोटे मूल्य वर्ग के नकद नोटों की मांग अभी भी अधिक बनी हुई है।

Ques : Which entity received in-principle approval for Payment Service Provider authorisation from IFSCA at GIFT-IFSC?

GIFT-IFSC में IFSCA से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्राधिकरण की सैद्धांतिक मंजूरी किस इकाई को मिली?

- A) Buyforex / बायफॉरेक्स
- B) Eraaya Lifespaces Limited / एराया लाइफस्पेसेज़ लिमिटेड
- C) EbixCash World Money / एबिक्सकैश वर्ल्ड मनी
- D) Ebix Forex Services / एबिक्स फॉरेक्स सर्विसेज
- E) GIFT City Payments Ltd / गिफ्ट सिटी पेमेंट्स लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- EbixCash World Money, a subsidiary of Eraaya Lifespaces Limited, announced that its wholly owned entity Buyforex received in-principle approval for Payment Service Provider authorisation from the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).
- Eraaya Lifespaces Limited की सहायक कंपनी EbixCash World Money ने घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई Buyforex को International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्राधिकरण की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
- The approval has been granted at Gujarat International Finance Tec-City – International Financial Services Centre (GIFT-IFSC).
- यह मंजूरी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी— इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर)GIFT-IFSC) में दी गई है।
- With this approval, Buyforex became the first Authorised Dealer Category-II (AD-II) licensed group entity to achieve this milestone.
- इस मंजूरी के साथ Buyforex यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली Authorised Dealer Category-II (AD-II) लाइसेंस प्राप्त समूह इकाई बन गई है।

Ques: RBI signed a MoU with which organisation to resolve long-standing bond clearing disputes?

RBI ने लंबे समय से चले आ रहे बॉन्ड क्लीयरिंग विवाद सुलझाने के लिए किस संगठन के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) European Securities and Markets Authority (ESMA) / यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण
- D) Bank for International Settlements (BIS) / अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
- E) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and information exchange related to Central Counterparties (CCPs).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ESMA) ने सेंट्रल काउंटरपार्टी (CCPs) से जुड़े सहयोग और सूचना आदान-प्रदान- MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU aims to resolve long-standing bond clearing disputes between Indian and European Union regulators.
- इस MoU का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के नियामकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बॉन्ड क्लीयरिंग विवाद को सुलझाना है।
- ESMA agreed to recognise the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) as a valid clearing party for EU banks.
- ESMA ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) को EU बैंकों के लिए वैध क्लीयरिंग संस्था के रूप में मान्यता देने पर सहमति दी।
- This recognition will allow European banks to seamlessly process bond and derivatives transactions through CCIL.
- इससे यूरोपीय बैंक CCIL के माध्यम से बॉन्ड और डेरिवेटिव लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।
- The dispute began in October 2022, when ESMA sought direct supervisory access to Indian clearing firms, which was opposed by the RBI.
- यह विवाद अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था, जब ESMA ने भारतीय क्लीयरिंग फर्मों पर प्रत्यक्ष निगरानी अधिकार की मांग की थी, जिसका RBI ने विरोध किया था।
- The new MoU replaces the earlier agreement of February 2017.
- यह नया MoU फरवरी 2017 में हुए पुराने समझौते का स्थान लेता है।
- The agreement supports smoother cross-border bond market operations and enhances financial stability.
- यह समझौता सीमासंचालन बाजार बॉन्ड पार- को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होगा।

Ques : The World Bank approved a loan of ₹5,700 crore for which project in Haryana?

विश्व बैंक ने हरियाणा में किस परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण मंजूर किया है?

- A) Jal Jeevan Mission Haryana / जल जीवन मिशन हरियाणा
 B) Jal Sanrakshit Haryana Project / जल संरक्षित हरियाणा परियोजना

- C) Namami Gange Haryana Extension / नमामि गंगे हरियाणा विस्तार
D) Atal Bhujal Yojana Haryana / अटल भूजल योजना हरियाणा
E) Har Khet Ko Pani Scheme / हर खेत को पानी योजना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has approved a loan of ₹5,700 crore for the Jal Sanrakshit Haryana Project.
 - विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
 - The objective of the project is to help Haryana achieve self-reliance in water resources.
 - इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा को जल संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाना है।
 - The loan amount will be disbursed in phases between 2026 and 2032.
 - यह ऋण राशि 2026 से 2032 के बीच चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
-

Ques : According to Swiss Re, which country is projected to be the fastest-growing major insurance market globally during 2026–2030?

स्विस री (Swiss Re) के अनुसार 2026–2030 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाजार होगा?

- A) China / चीन
B) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
C) South Africa / दक्षिण अफ्रीका
D) Brazil / ब्राज़ील
E) India / भारत

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- According to Swiss Re, India's insurance premiums are projected to grow at a

real annual rate of 6.9% during 2026–2030, making India the fastest-growing major insurance market globally.

- Swiss Re के अनुसार 2026–2030 के दौरान भारत के बीमा प्रीमियम में वास्तविक वार्षिक 6.9% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाजार बन जाएगा।

- India's insurance growth rate is significantly higher than China (around 4%) and the United States (around 2%).

- भारत की बीमा वृद्धि दर चीन (लगभग 4%) और अमेरिका (लगभग 2%) से काफी अधिक है।

- This growth marks a strong rebound from slower growth of only 3.1% in 2025, when the market adjusted to new regulations.

- यह वृद्धि 2025 में नए नियमों के समायोजन के कारण दर्ज की गई 3.1% की धीमी वृद्धि के बाद मजबूत वापसी को दर्शाती है।

- In life insurance, India is the second-largest market among emerging economies, with expected annual growth of 6.8% over the next five years, driven by expanding distribution networks.

- जीवन बीमा क्षेत्र में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां अगले पांच वर्षों में 6.8% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, जिसका कारण वितरण नेटवर्क का विस्तार है।

- Health insurance in India is expected to grow at an average rate of 7.2% per year during 2026–2030.

- भारत में स्वास्थ्य बीमा के 2026–2030 के दौरान औसतन 7.2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

EXAM
Genius